ANSWER BOOK
उत्तर पुस्तिका

Roshni Kumari

PAPER (2) - [PART - 1]

Date - 15/01/2021

1 (a) सहकारी संघवाद

सहकारी संघवाद अवधारणा के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य के बीच टकराव की बजाय पारस्परिक सहयोग व सामंजस्य के साथ सीमित संसाधनों का प्रयोग कर विकास की प्रक्रिया को तीव्र करता है।

1 (b) सीनेट

अमेरिका के उच्च सदन को सीनेट कहते है। जिसमें 100 सदस्य हैं। प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि लिये जाते हैं।

1 (c) अनुच्छेद - 275

इसके अन्तर्गत संसद को यह अधिकार है कि राज्यों विधिक अनुदान दे। विधिक अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दिये जाते है ये राशि अलग अलग राज्यों के लिये अलग अलग हो सकती है।

1 (d) परमादेश

सर्वोच्च न्यायालय की रिट द्वारा जारी की जाने वाली रिट जिसमें जो किसी सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध उसके स्व कृत्यों का निर्वहन न करने पर जारी की जाती है।

1 (e) आच्छादन का सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार संसद द्वारा निर्मित विधि जो मूल अधिकारो के संगत न हो, वह उस सीमा तक लागू नहीं होगी जहां तक वह मूल अधिकारों को प्रभावित करती है।

Scanned by CamScanner

प्रत्यानुदान

1 F अनुदान जो सरकार को किसी आकस्मिक व्यय हेतु प्रदान किया जाता है, इसे सरकार को ब्लैंक चेक भी कहते हैं।

1 G लोकसभा में विपक्ष का नेता – जो 10% सीट प्राप्त करता है। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के बाद जिस दल के सर्वाधिक सदस्य होते हैं वह विपक्ष के नेता के रूप में ~~नियुक्त~~ हो, एक सदस्य को नियुक्त करता है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है।

1 H केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
संविधान के अनु० 323(क) के अन्तर्गत प्रावधान है भाग-14 (क); केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधि० 1985 द्वारा गठित केन्द्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्य विवाद समाधान हेतु

1 I 97वां संविधान संशोधन
97 संविधान संशोधन अधि० 2011 द्वारा भाग-9ख जोड़ा जिसमें सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान है।

1 J सिविल अधिकार संरक्षण अधि० की धारा 15(A)

प्रश्न क्रमांक तथा उपक्रमांक अंकित करें

1(K) राज्य मानवाधिकार आयोग

मानव अधिकार संरक्षण अधि० 1993 के तहत गठित। कार्यक्षेत्र – राज्य स्तर पर, बहुसदस्यीय निकाय, कार्यकाल – 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु कार्य – मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना।

1(L) अनुच्छेद 335

अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिये विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान

(M) मतदाता फोटो पहचान पत्र

मतदाताओं (18 वर्ष से अधिक) को मत देने संबंधी पहचान पर फोटो का अंकन, ताकि निर्वाचन में फर्जी मतदान को रोका जा सके।

(N) गैर सरकारी संगठन

~~आपसी सहयोग से एक छोटे क्षेत्र में समान स्तर~~ ऐसे संस्थान जो पूर्णतय से स्वयत्त शासी, सरकारी नियंत्रण से मुक्त गैर लाभकारी संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य समाज कल्याण, पर्यावरण संरक्षण ~~लोगों~~ ~~आदि का मताधिकार~~ या सार्वजनिक हित से संबद्ध होता है। भारत में तीन प्रकार –

परंपरागत NGO, सक्रियतावादी, व रिसर्च संस्थान NGO

2(ग) राज्य महाधिवक्ता

राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, व विभिन्न मामलो मे राज्य की ओर से पैरवी करता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा।

PMST ACADEMY
ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं

Question number and subsection number inside the boxes
दस में प्रश्न क्रमांक तथा उपक्रमांक अंकित करें

2 A वित्तीय आपात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये -
संविधान के अनु 360 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व संबंधी खतरे की स्थिति में घोषित किया जाता है।

उद घोषणा से प्रभाव =>

(1) राष्ट्रपति केन्द्र-राज्य के मध्य राजस्व संबधी प्रावधानों में परिवर्तन कर सकता है
(2) ~~सर्वोच्च~~ SC उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों, राज्य के अधीन अधिकारी कर्मचारी के वेतन भत्तों में कटौति कर सकता है।
(3) राज्य धन विधेयकों को अपने पास सुरक्षित।

2 B CAG की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान
प्रमुख प्रावधान -
(1) निश्चित कार्यकाल (6 वर्ष), एवं कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों, सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं।
(2) CAG को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय को।
(3) सेवा निवृत्ति के पश्चात केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं।
(4) ?

अपूर्ण

नागरिक चार्टर क्या है, बेहतर बनाने के सुझाव दीजिए।

ऐसा दस्तावेज जो शिकायत निवारण तंत्र के साथ मानक सेवा वितरण, गुणवत्ता और समयावधि के प्रति सार्वजनिक निकायों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है।

नागरिक चार्टर बेहतर बनाने के सुझाव:
- → चार्टर सरल भाषा में हो
- → नागरिकों / उपभोक्ताओं से विचार विमर्श
- → अनुपालन सुनिश्चित न होने पर दण्ड का प्रावधान
- → शिकायतों के समाधान हेतु उपयुक्त तंत्र बनाने की आवश्यकता है
- → प्रत्येक लोक प्राधिकारी के दायित्वों व उनके द्वारा किये जाने कार्य की समयसीमा का प्रावधान हो

2 (b) स्व सहायता समूहों की विकासात्मक गतिविधि में भूमिका।

छोटे स्तर पर समान स्तर के लोगों द्वारा तथा समान समस्याओं के समाधान हेतु गठित गरीब वंचित लोगों का समूह — SHG

विकासात्मक गतिविधि में भूमिका —

(1) आर्थिक स्वावलंबन एवं आर्थिक रूप से गरीब वंचितों को सशक्त किया।

(2) महाजनी ऋण से छुटकारा, एवं महिला सशक्तीकरण

(3) सामाजिक समावेशन एवं क्रय शक्ति क्षमता में

(4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये त्वरित आवश्यकता पूर्ति एवं रोजगार साधनों का विकास

(5) बचत प्रवृत्ति व पूंजी संग्रहण में वृद्धि।

प्रश्न प्रश्नांक तथा उपप्रश्नांक अंकित करें

6 भारत सरकार अधि॰ 1935 के प्रमुख प्रावधान

(1) केन्द्र मे द्वैध शासन – गवर्नर व कार्यकारणी को आरक्षित विषय तथा गवर्नर एवं मंत्रिपरिषद को हस्तांतरित विषय

(2) प्रांतों मे उत्तरदायी शासन का विकास

(3) केन्द्र व कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का गठन जिसमे निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक।

(4) संघीय न्यायालय का गठन

(5) संघीय बैंक RBI का प्रावधान

(6) बंबई से अलग कर सिंध को नया प्रांत बनाया

(7) बर्मा को भारत से अलग किया।

7 संविधान संशोधन के व्यसद के अधिकार पर SC का नियंत्रण

संविधान के अनु॰ 368 के प्रावधानो में संशोधन कर संसद ने संविधान की संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त की परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला (24 अप्रैल 1973) में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया जिसके अन्तर्गत संसद यदि मूल ढांचे को संशोधित करने का प्रयास करेगी तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकेगा।

संविधान के अनु॰ 32, 226 से प्राप्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तथा मूलढांचे की अवधारणा ने संसद की संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया है।

Scanned by CamScanner

प्रश्न क्रमांक तथा उपप्रश्नांक अंकित करें

2 ख भारत के संविधान में एकीकरण के तत्वों का उल्लेख करें।

एकीकरण के तत्व –

(1) केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति

(2) अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र में निहित

(3) आपात उपबंध → राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन

(4) राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा विधि बनाना

(5) राज्यों की सीमा, नाम परिवर्तन

(6) एकल नागरिकता

(7) एकीकृत लेखा जांच मशीनरी

(8) एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था

(9) संविधान का लचीलापन

(10) अखिल भारतीय सेवायें।

3 I लोक तंत्र के चौथे स्तम्भ के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन

लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया के समक्ष प्रमुख चुनौतियां –

(1) मीडिया पूरी तरह व्यवसायिक हो गई अतः विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हुआ।

(2) राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति असंवेदनशील,

(3) प्रमुख लक्ष्य जनता को जागरूक करना नहीं, अपितु TRP बढ़ाना रह गया है

(4) स्टिंग ऑपरेशन के साथ निजता पर

(5) प्रहार एवं केवल आलोचना करना प्रमुख लक्ष्य

(6) किसी दल विशेष के प्रति झुकाव

(7) निष्पक्ष व तटस्थ पत्रकारिता का अभाव।

14 संविधान के बुनियादी ढांचे से आप क्या समझते हैं

संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती मामले (1973) में दिया इसके शामिल प्रमुख तत्व =

(1) संविधान की सर्वोच्चता
(2) लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक ढांचा
(3) धर्मनिरपेक्षता, लोककल्याणकारी राज्य
(4) विधि का शासन, भारत की संप्रभुता
(5) राष्ट्र की एकता व अखण्डता
(6) न्यायिक पुनर्विलोकन
(7) संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति
(8) सामाजिक, आर्थिक, न्याय

15 लोकसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी कीजिए

संसद के सदस्यों में से बहुमत के आधार पर चुना जाता है।

कार्य - (1) सदन की कार्यवाही नियंत्रण करना
(2) कार्य संचालन, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता।
(3) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।
(4) लोकसभा बैठकों की तिथि निर्धारित करना
(5) सदन में किसे बोलना है यह निर्धारित करना
(6) धन विधेयक का निर्धारण
(7) दलबदल निरर्हता संबंधी सदस्यों की अंतिम निर्णय करना।

Scanned by CamScanner

...स में प्रश्न क्रमांक तथा उपक्रमांक अंकित करें

3 (1) अध्यक्षीय व संसदीय शासन प्रणाली मे तुलनात्मक बिन्दु —

अध्यक्षीय शासन	संसदीय शासन
(1.) राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक व कार्यकारी प्रमुख होता है	(1.) राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता।
(2.) शासन की शक्ति राष्ट्रपति के केन्द्रित होती है	(2.) ~~राष्ट्रपति राज्य~~ शासन संचालन का केन्द्र प्रधानमंत्री होता है
(3.) राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त कैबिनेट के सचिवों द्वारा शासन करता है	(3) प्रधानमंत्री अपनी मंत्रीमंडल के माध्यम से शासन करता है
(4) राष्ट्रपति ~~स्वतंत्र~~ किसी सदन का सदस्य नही होता	प्रधानमंत्री ~~किन्हें~~ संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है
(5) राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है	राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव

MST ACADEMY ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं

Scanned by CamScanner

(6) शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है यहां कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है

(6) कार्यपालिका, विधायिका के अंदर से निर्मित होती है

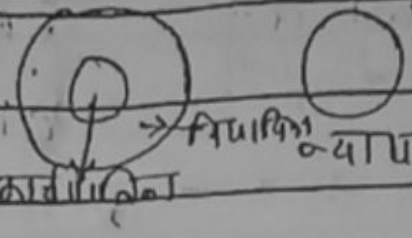

(7) राष्ट्रपति के महाभियोग या पद रिक्ति के बाद उपराष्ट्रपति शेष समय के लिये राष्ट्रपति बनता है

(8) राष्ट्रपति की पद रिक्ति के बाद उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति पद संभालता है।

ACADEMY
ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितं

अनुक्रमांक तथा उपप्रश्नांक अंकित करें

3 (2) निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन –

संविधान के अनु. 324 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है

संरचना – एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त । दो अन्य निर्वाचन आयुक्त

नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा

कार्यकाल – 6 वर्ष / 65 वर्ष ।

निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य –

(1) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधान मण्डल के संसद के चुनावों में विवादों में ~~प्रशासनिक~~ न्यायिक सलाहकारिता ~~एवं सम्बन्ध~~

(2) संसद, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करवाना।

(3) मतदाता सूची तैयार करना, पुनरीक्षण एवं नवीनीकरण करना

(4) राजनीतिक दलों के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता का निर्माण करना।

(5) निर्वाचन की तिथि, नामांकन तिथि, चुनावी परिणामों की घोषणा, मतगणना करना।

(6) ~~स्वतंत्र~~ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना।

(7) राज्यों में प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा निर्वाचन के हेतु अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(8) राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना एवं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना।

(9) राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को दर्जा देना।

(10) चुनावी व प्रशासनिक मशीनरी हेतु राज्य/केन्द्र सरकार से अनुमोदित करना।

(11) मीडिया का विनियमन करना

(12) राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन पर दण्डित करना।

Scanned by CamScanner

(13) लोकसभा को चुनाव सुधार संबंधी सिफारिश करना।

(4) इस प्रकार चुनाव आयोग संसद व राज्य विधान मंडल के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु प्रमुख रूप से जिम्मेदार संस्था है जो लोकतंत्र के निर्धारण हेतु प्रमुख संस्था है।

FAST ACADEMY

मौलिक निदेशक तत्वों की विशेषताओं के साथ प्रमुख नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख

नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान संविधान के भाग 4 के अनु 36 से अनु 51 तक है।

नीति निदेशक तत्वों की विशेषताएं :—

(1) नीति निदेशक तत्व न्यायालय में अप्रवर्तनीय होते हुये भी मूलभूत महत्व के हैं।

(2) मूल अधिकारों के पूरक हैं।

(3) सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं।

(4) बिना आर्थिक, सामाजिक अधिकारों के राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है।

(5) राज्यों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं।

(6) ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं।

(7) सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा सुनिश्चित करते हैं।

(8)

प्रमुख नीति निर्देशक तत्व -

(1) अनु० 38 - राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा जहाँ सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित हो सके।

अनु० 38 - आय सुविधा तथा अवसर की समानता प्रदान करेगा।

अनु 39 (क) पुरुषों व स्त्रियों को समान अधिकार
(क) आजीविका के समान अवसर
(ख) समान कार्य के लिये समान वेतन
(ग) भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण
(घ) धन का विकेन्द्रीकरण को रोकना

अनु० 40 - पंचायतों का गठन

अनु० 39 क - निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना ताकि गरीबों वंचितों की न्याय तक समान पहुँच हो।

अनु० 42 - काम की मानवोचित दशाये तथा गर्भवती स्त्रियों को प्रसूति अवकाश।

Scanned by CamScanner

अनु० 43 – उद्योग के कर्मियों को न्यूनतम जीवन स्तर, अवकाश आदि की सुविधा प्रदान करना

अनु 43क सहकारी समितियों की स्थापना

अनु 44 – सामान नागरिक संहिता लागू करना।

अनु 45 – 0-6 वर्ष तक के बच्चों को लिये शिक्षा हेतु प्रयास करना।

अनु० 47 – नागरिकों को पोषण स्तर सुनिश्चित करना एवं नशीली वस्तुओं के प्रयोग को कम करना।

अनु० 48 – पशुओं की नस्ल सुधार

अनु 49 राष्ट्रीय स्मारकों, वस्तुओं, स्थानों की सुरक्षा करना

अनु 50 – न्यायपालिका के कार्यों से कार्यपालिका का पृथक्करण

अनु० 51 – अन्तर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाये रखना।

10